



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

PM-KUSUM योजना का पुनर्मूल्यांकन

www.nextias.com

PM-KUSUM योजना का पुनर्मूल्यांकन

संदर्भ

- चूंकि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (PM-KUSUM) योजना अपने लक्ष्य वर्ष 2026 के निकट पहुंच रही है, इसलिए चुनौतियों का समाधान करने और किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में इसके प्रभाव को अनुकूलित करने के लिए पुनर्संयोजन आवश्यक है।

PM-KUSUM के संबंध में

- इसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डीजल पर निर्भरता कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देना सहित कई उद्देश्यों को प्राप्त करना है।
- पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य तीन प्रमुख घटकों के माध्यम से किसानों की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना है।
 - ◆ घटक A का लक्ष्य बंजर भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है, जिसमें फीड-इन टैरिफ पर डिस्कॉम को विद्युत विक्रय की जाएगी।
 - ◆ घटक B ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 17.50 लाख स्टैंडअलोन सौर कृषि पंप स्थापित करने पर केंद्रित है, जिसमें 30% केंद्रीय सहायता, 30% राज्य सब्सिडी और 40% किसानों को योगदान दिया जाएगा।
 - ◆ घटक C 10 लाख ग्रिड से जुड़े पंपों के सौरीकरण का समर्थन करता है, जिससे किसान सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अधिशेष विद्युत डिस्कॉम को बेच सकते हैं।

मुख्य लाभ

- **सामाजिक-आर्थिक लाभ:** हाशिए पर पड़े किसानों को सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा उपलब्ध कराता है।
 - ◆ महंगे डीजल और अनियमित ग्रिड आपूर्ति पर निर्भरता कम हो जाती है।
 - ◆ किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता करना।
 - ◆ डिस्कॉम को बेची गई अधिशेष ऊर्जा से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न होता है।
 - ◆ परिचालन लागत में कटौती, तथा लाभप्रदता में वृद्धि।
 - ◆ सौर अवसंरचना की स्थापना, रखरखाव और संचालन के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 32 मिलियन टन CO₂ की कमी आती है।
 - ◆ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
 - ◆ पंचामृत लक्ष्यों के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाता है।
- **तकनीकी लाभ:**
 - ◆ सौर प्रौद्योगिकी और आपूर्ति शृंखला में नवाचार को बढ़ावा देता है।
 - ◆ कम रखरखाव वाले सौर पंपों और हाइब्रिड प्रणालियों को अपनाने को प्रोत्साहित करता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **कार्यान्वयन में बाधाएँ:** धीमी प्रगति, जैसे 2024 तक केवल 30% लक्ष्य प्राप्त किया जाना।
 - ◆ केंद्रीकृत कार्यान्वयन ने क्षेत्र विशेषज्ञता वाली स्थानीय एजेंसियों को दरकिनार कर दिया है।
- **वहनीयता और पहुँच:** सब्सिडी के बावजूद, उच्च प्रारंभिक लागत इसे अपनाने में बाधक है, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के बीच।

- **सब्सिडी वाली बिजली की उपलब्धता:** किसानों को भारी सब्सिडी वाली बिजली मिलने से सौर पंप अपनाने के प्रति उनका प्रोत्साहन कम हो जाता है।
- किसानों को दी जाने वाली भारी सब्सिडी वाली बिजली, सौर पंप अपनाने के प्रति उनके प्रोत्साहन को कम कर देती है।
- **तकनीकी एवं तार्किक मुद्दे:** पंप क्षमताओं में एकरूपता का अभाव और रखरखाव संबंधी बुनियादी ढाँचे का खराब होना।
- **डिस्कॉम के साथ एकीकरण:** वित्तीय रूप से संकटग्रस्त डिस्कॉम किसानों से अधिशेष सौर ऊर्जा खरीदने से परहेज करते हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** हरियाणा और राजस्थान जैसे बेहतर बुनियादी ढाँचे वाले राज्य बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

सफलता की कहानियाँ और संभावनाएँ

- पीएम-कुसुम ने कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत को कम करने में योगदान दिया है, और किसानों को ऊर्जा का एक विश्वसनीय और टिकाऊ स्रोत प्रदान किया है।
 - ◆ सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर, पीएम-कुसुम योजना 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
- बिहार की 'सोलर दीदी' के नाम से मशहूर देवकी देवी और सुनीता देवी जैसी लाभार्थियों को स्थानीय सरकारी कार्यक्रमों और आगा खान ग्रामीण सहायता कार्यक्रम (भारत) से लाभ मिला है।
 - ◆ उनके अनुभव कृषि पद्धतियों में परिवर्तन लाने में सौर ऊर्जा की क्षमता को रेखांकित करते हैं।

प्रमुख अनुशासनाएँ (पुनः अंशांकन की आवश्यकता)

- **विकेंद्रीकरण:** क्षेत्रीय आवश्यकताओं और स्थितियों के आधार पर योजना को लागू करने के लिए स्थानीय एजेंसियों को सशक्त बनाना।
- **सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहन:** सस्ती बिजली के मुद्दे पर ध्यान देकर किसानों को सौर पंप अपनाने के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना।
- **घटक A और C पर अधिक ध्यान:** सभी घटकों में संतुलित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए घटक A और C के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना।
- **डिस्कॉम व्यवहार्यता:** अधिशेष विद्युत की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए डिस्कॉम के लिए नीतिगत प्रोत्साहन लागू करना।
- **राज्य-विशिष्ट रणनीतियाँ:** समान वितरण और कुशल कार्यान्वयन के लिए राज्य-स्तरीय योजनाएँ विकसित करना।

निष्कर्ष

- पीएम-कुसुम योजना में भारत की जलवायु कार्रवाई को गति देने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की क्षमता है।
- हालाँकि, इस क्षमता को साकार करने के लिए, कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करना और 2026 तक अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए योजना को पुनः व्यवस्थित करना महत्वपूर्ण है।

Source: BL



दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

पीएम-कुसुम योजना के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय महत्त्व का विश्लेषण कीजिए। इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और बेहतर परिणामों के लिए योजना को पुनः समायोजित करने के तरीके सुझाइए।